Daily Current Affairs
24 April 2023

Index

- भारत-कैरीकॉम मंत्रिस्तरीय बैठक
- लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) 2023
- प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना।
- ई-ग्राम स्वराज और जीईएम पोर्टल
- भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023
- प्रयाग प्लेटफॉर्म
- यूपी 100% सरकारी विभाग में इलेक्ट्रिक वाहन के साथ पहला भारतीय राज्य बनने की राह पर है
- बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस शांति के लिए

Important News: International

1. भारत-कैरीकॉम मंत्रिस्तरीय बैठक

चर्चा में क्यों:- भारत के विदेश मंत्री ने जमैका के अपने समकक्ष के साथ चौथी भारत-कैरीकॉम मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की।

A.कैरिकॉम, जो कैरिबियन समुदाय के लिए खड़ा है, विकासशील दुनिया में सबसे पुराना जीवित एकीकरण आंदोलन है।

B.कैरेबियाई देशों और निर्भरताओं का एक संगठन है जिसे मूल रूप से 1973 में चगुआरामस की संधि द्वारा कैरिबियन समुदाय और कॉमन्स बाजार के रूप में स्थापित किया गया था।

C.उद्देश्य: **a.**सदस्यों के बीच आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा

b.To सुनिश्चित करते हैं कि एकीकरण के लाभ समान रूप से साझा किए जाते हैं;

c.विदेश नीति का समन्वय।

D.इसमें में 15 सदस्य हैं; एंटीगुआ और बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, ग्रेनेडा, गुयाना, हैती, जमैका, मोंटसेराट, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो, एंगुइला, बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमैन आइलैंड्स और तुर्क और कैकोस आइलैंड्स को सहयोगी सदस्यों का दर्जा प्राप्त है।

E.समुदाय की अध्यक्षता सदस्य राज्यों के प्रमुखों के बीच हर छह महीने में घूमती है। जॉर्जटाउन, गुयाना में कैरिकॉम सचिवालय, समुदाय का प्रमुख प्रशासनिक अंग है और इसका नेतृत्व एक महासचिव द्वारा किया जाता है जो समुदाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

F. 2007 में, कैरिकॉम ने आधिकारिक तौर पर कैरेबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस (सीसीजे) का उद्घाटन किया, जो कैरीकॉम सदस्यों के लिए अपील की अंतिम अदालत के रूप में कार्य करता है और क्षेत्रीय व्यापार विवादों को भी संभालता है।

(SOURCE – ECONOMIC TIMES)

2. लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) 2023

चर्चा में क्यों:- हाल ही में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक में छह स्थानों का सुधार हुआ है।

A.विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है जो देशों को व्यापार रसद पर अपने प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है।

B.विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला कनेक्शन और संरचनात्मक कारकों की स्थापना में आसानी को मापता है जो इसे संभव बनाते हैं, जैसे रसद सेवाओं की गुणवत्ता, व्यापार और परिवहन से संबंधित बुनियादी ढांचे, साथ ही सीमा नियंत्रण।

C.LPI 2023 139 देशों में तुलना की अनुमति देता है।

D.डीएलपीआई 2023, पहली बार, शिपमेंट को ट्रैक करने वाले बड़े डेटासेट से प्राप्त संकेतकों के साथ व्यापार की गति को मापता है।

सिंगापुर और फिनलैंड 2023 एलपीआई के अनुसार सबसे कुशल और उच्चतम रैंक वाले एलपीआई देश हैं।

E.भारत 139 देशों में से 38 वें स्थान पर है, जो पिछले सूचकांक से छह स्थान ऊपर है।

F.सूचकांक में भारत की उछाल के दो प्रमुख चालक आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण हो सकते हैं, जिसे रिपोर्ट में भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के उन्नत देशों से आगे निकलने का कारण बताया गया है।

(SOURCE – INDIAN EXPRESS)

3. प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना।

चर्चा में क्यों:-हाल ही में, प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन के बिहार भाग को पूरा करने की प्रशंसा की।

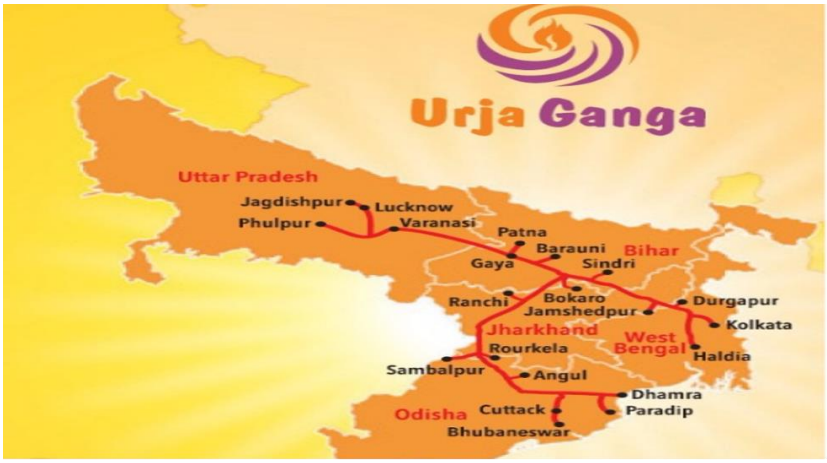

A.इस परियोजना को जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन परियोजना (जेएचबीडीपीएल) परियोजना के नाम से भी जाना जाता है।

B.यह 2016 में शुरू किया गया था और पांच राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

C.यह पाइपलाइन बिहार के छह जिलों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी। यह परियोजना उद्योगों के लिए स्वच्छ प्राकृतिक गैस, वाहनों के लिए सीएनजी और घरों के लिए पीएनजी तक पहुंच प्रदान करेगी, एक स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देगी।

D.प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत पाइपलाइन की कुल लंबाई 3,384 किमी है, जिसमें से 766 किमी पाइपलाइन ओडिशा राज्य में है और शेष 2,618 किमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में है।

E.सात मुख्य स्टेशन शहरों में वाराणसी, पटना, बोकारो, जमशेदपुर, कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर और कटक परियोजना के प्रमुख लाभार्थियों के रूप में शामिल हैं।

F.यह परियोजना गेल द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(SOURCE – INDIAN EXPRESS)

4. ई-ग्राम स्वराज और जीईएम पोर्टल

चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर और भारत में पंचायती राज के 30 साल पूरे होने के अवसर पर, प्रधान मंत्री मध्य प्रदेश के रीवा में पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एक एकीकृत ई-ग्राम स्वराज और जीईएम पोर्टल का उद्घाटन करेंगे।

A.ई-ग्राम स्वराज-जीईएम एकीकरण का उद्देश्य पंचायतों को ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर जीईएम के माध्यम से अपनी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने में सक्षम बनाना है।

B.यह पूरे क्रेता-विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र को फलने-फूलने में मदद करेगा, जिससे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को मजबूत करने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्यमिता को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

C.जीईएम के मौजूदा उपयोगकर्ता आधार को चरणबद्ध तरीके से लगभग 60,000 से बढ़ाकर 3 लाख से अधिक करने की परिकल्पना की गई है। और प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर पंचायतों द्वारा खरीद में पारदर्शिता लाना।

D.स्थानीय विक्रेताओं (मालिकों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, आदि) को जीईएम पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना क्योंकि पंचायतें बड़े पैमाने पर ऐसे विक्रेताओं से खरीदती हैं।

E.पंचायतों को मानकीकृत और प्रतिस्पर्धी दरों पर गुणवत्ता-सुनिश्चित वस्तुओं की डोरस्टेप डिलीवरी तक पहुंच होगी।

(SOURCE – INDIAN EXPRESS)

Important News: National

5. भारतीय अंतरिक्ष नीति (आईएसपी) 2023

चर्चा में क्यों:- सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और निजी कंपनियों से अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष नीति (आईएसपी) 2023 को मंजूरी दे दी है।

A.भारत वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 2% हिस्सा है (संयुक्त राज्य अमेरिका की 50% से अधिक हिस्सेदारी है)

B.भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का मूल्य 2019 में $ 7 बिलियन था और 2024 तक $ 50 बिलियन तक बढ़ने की इच्छा रखता है। भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी लागत-प्रभावशीलता का उपयोग करने की आवश्यकता है

C.नीति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), अंतरिक्ष क्षेत्र के पीएसयून्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल), और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है।

A.अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित रणनीतिक गतिविधियों को एनएसआईएल द्वारा किया जाएगा, जो मांग-संचालित मोड में काम करेगा।

b.IN-SPACE ISRO और गैर-सरकारी संस्थाओं के बीच इंटरफेस होगा।

c.इसरो नई प्रौद्योगिकियों, नई प्रणालियों और अनुसंधान और विकास के विकास पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करेगा।

d.इसरो के मिशनों के परिचालन हिस्से को न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

D. इस नीति से भारत को भविष्य में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी 2% से कम से बढ़ाकर 10% करने में मदद मिलेगी।

(SOURCE –NEWS ON AIR)

6. प्रयाग प्लेटफॉर्म

चर्चा में क्यों:- यमुना, गंगा और उनकी सहायक नदियों के वास्तविक समय के विश्लेषण के लिए प्रयाग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया।

A.जल शक्ति मंत्रालय ने परियोजनाओं, नदी जल की गुणवत्ता आदि की योजना और निगरानी के लिए एक वास्तविक समय निगरानी केंद्र प्रयाग का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के

अधिकार प्राप्त कार्यबल की 11वीं बैठक के दौरान।

B.प्रयाग (यमुना, गंगा और उनकी सहायक नदियों के वास्तविक समय के विश्लेषण के लिए मंच) विभिन्न ऑनलाइन डैशबोर्ड जैसे गंगा तरंग पोर्टल, गंगा जिला प्रदर्शन निगरानी प्रणाली आदि के माध्यम से विभिन्न

परियोजनाओं की निगरानी करता है।

C.एन.एम.सी.जी.(2011; एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में) का उद्देश्य मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्रों का पुनर्वास और संवर्धन करना है;

D.NMCG का उद्देश्य मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्रों का पुनर्वास और बढ़ावा देना है; निकास बिंदुओं पर प्रदूषण पर अंकुश; प्राकृतिक विविधताओं को बदलने के बिना पानी के प्रवाह को बनाए रखें; सतह और भूजल आदि को बहाल करना। गंगा और उसकी सहायक नदियों में। यह राष्ट्रीय गंगा परिषद राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन **(NMCG)** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है

(SOURCE –NEWS ON AIR)

Important News: States

7.यूपी 100% सरकारी विभाग में इलेक्ट्रिक वाहन के साथ पहला भारतीय राज्य बनने की राह पर है

चर्चा में क्यों:- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस पहल के हिस्से के रूप में, सरकार ने 2030 तक चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों को ईवी में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

A.उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों को गैर-निविदा नामांकन आधार पर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदकर उनके उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग अपनी जरूरत के हिसाब से ईवी खरीदने के लिए अधिकतम सीमा से अधिक खर्च भी कर सकते हैं।

B.2030 से पहले सभी सरकारी वाहनों को ईवी में बदलने के लक्ष्य

को प्राप्त करने के **B.By,** उत्तर प्रदेश का लक्ष्य देश का पहला राज्य बनना है, जिसके सरकारी विभागों में 100% ईवी हैं।

C.ईवी को अपनाने को प्रोत्साहित **C.To** के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 को भी अधिसूचित किया है।

D. नीति में निम्नलिखित प्रोत्साहन शामिल हैं:

a. ईवी की खरीद पर तीन साल के लिए टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट।

b.राज्य में निर्मित ईवी की खरीद पर पांच साल के लिए कर और पंजीकरण शुल्क से छूट।

(SOURCE – NEWS ON AIR)

Important News: Days

7. बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस शांति के लिए

चर्चा में क्यों: 24 अप्रैल को, बहुपक्षवाद और शांति के लिए कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ग्रह के चारों ओर मनाया जाता है।

A.यह दिन देशों के बीच संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान को प्राप्त करने के लिए बहुपक्षीय कूटनीति और निर्णय लेने के उपयोग को स्वीकार करता है।

B.यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, कूटनीति और बहुपक्षीय तंत्र के उपयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और दुनिया में युद्धों के अंत को बढ़ावा देता है।

C.इस दिन को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए घोषित किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद के मूल्यों को संरक्षित करना संयुक्त राष्ट्र के तीन स्तंभों के प्रचार और समर्थन के लिए मौलिक है:
शांति और सुरक्षा
विकास
मानवाधिकार।

D. यह दिन शांतिपूर्ण तरीकों से दुनिया के देशों के बीच विवादों को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर और इसके सिद्धांतों की पुष्टि करता है। यह दिवस पहली बार 2018 में स्थापित होने के बाद वर्ष 2019 में मनाया गया था।

E.इस दिन का उद्देश्य शांति के लिए कूटनीति और बहुपक्षवाद के फायदों के बारे में ज्ञान पैदा करना और फैलाना है, जिसमें सार्वजनिक और शैक्षिक जागरूकता के माध्यम से गतिविधियों को बढ़ाना शामिल है।

F.इस दिन का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को युद्ध की कठिनाइयों से बचाने और शांतिपूर्ण तरीके से विवाद निपटान के माध्यम से इसे प्राप्त करने के संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत उद्देश्य को बढ़ावा देना है।

(SOURCE – NEWS ON AIR)